

रेपो रेट में कटौती और इसके नहितार्थ

प्रलिस के लयि:

मौद्रकि नीतिसमिति (MPC), मुद्रास्फीति, वैयक्तिक आयकर, रेपो रेट, ब्याज दर, थोक मूल्य सूचकांक (WPI), M3 मुद्रा आपूर्ति

मेन्स के लयि:

रेपो रेट और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव ।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतिसमिति (MPC) ने 5 वर्षों में (वर्ष 2020 से) पहली बार रेपो रेट को 6.5% (25 आधार अंक (BPS)) से घटाकर 6.25% कर दिया ।

- केंद्रीय बजट 2025-26 में उपभोग को बढ़ावा देने के लिये वैयक्तिक आयकर में कटौती के बाद, इस कदम का उद्देश्य मंदी के बीच आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना है ।

RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के नरिणय के पीछे क्या कारण थे?

- विकास को बढ़ावा देने वाला बजट: केंद्रीय बजट 2025-26 में वैयक्तिक आयकर में कटौती और TDS सीमा में संशोधन किया गया, जिससे प्रयोज्य आय में वृद्धि हुई ।
 - RBI की रेपो रेट में कटौती, उधार लागत को कम करके और मांग को बनाए रखकर सरकार की कर कटौती का समर्थन करती है ।
- घटती मुद्रास्फीति: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) दिसंबर 2024 में घटकर 5.22% हो गया, जो चार महीने का नमिनतम स्तर है, जबकि नवंबर में यह 5.48% था, जो मौद्रिक सुलभता (Monetary Easing) के लिये रकित प्रदान करता है ।
- बाज़ार तरलता वृद्धि: RBI ने हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में तरलता सुधारने के लिये 1.5 ट्रिलियन रुपए की पूंजी डालकर उपाय शुरू किये हैं ।
 - तरलता के प्रवाह ने महंगे ऋण बाज़ारों को सुलभ बना दिया, जबकि रेपो दर में कटौती ने तरलता सुनिश्चिती की और विकास को बढ़ावा देने के लिये ब्याज दरें कम कर दीं ।
- वैश्विक आर्थिक अनश्चितिता: कनाडा, मैक्सिको और चीन पर हाल ही में अमेरिकी टैरिफि ने व्यापार युद्ध की आशंकाओं को जन्म दिया, जिससे रुपया कमज़ोर होकर 87.29 प्रति डॉलर पर आ गया और मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ गया ।
 - रेपो रेट में कटौती से बाह्य आघातों के प्रभाव को कम करने तथा घरेलू विकास को समर्थन देने में मदद मिल सकती है ।

रेपो रेट क्या है?

- रेपो रेट (रिपिचेज़ एग्रीमेंट रेट) वह ब्याज दर है, जिस पर वाणजियिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं ।
- उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली: ऋण लेकर, यह बैंकों को उनकी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है ।
 - बैंक प्रतभूतियाँ लघु-अवधि के रूप में उपलब्ध कराते हैं तथा बाद में उन्हें अधिक कीमत पर (ब्याज सहित) पुनर्खरीद (रिपिचेज़) करने पर सहमत होते हैं ।
- ऋण लेने की लागत पर प्रभाव:
 - उच्च रेपो रेट → बैंकों के लिये महंगे ऋण → उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिये उच्च ब्याज दरें → उधार लेने और व्यय करने की धीमी प्रक्रिया ।
 - कम रेपो रेट → बैंकों के लिये सस्ता ऋण → उधारकर्ताओं के लिये कम ब्याज दरें → उधार और व्यय में वृद्धि ।
- मौद्रिक नीति में भूमिका: इसका उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा धन की आपूर्ति, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को नियंत्रित करने के लिये किया जाता है ।

रेपो रेट में कटौती के क्या नहितारथ हैं?

- **आर्थिक विकास:** कम ऋण लागत से व्यवसायों के लिये वसितार और नविश करना आसान हो जाता है, जिससे उत्पादन और रोजगार सृजन में वृद्धि होती है।
 - रेपो रेट में कटौती से ब्याज दरें कम हो जाती हैं, ऋण सस्ते हो जाते हैं, EMI कम हो जाती है, तथा ऋण लेने और खर्च करने में वृद्धि होती है।
- **वित्तीय बाजारों को मज़बूत करना:** बैंक बचत खातों और सावधि जमाओं पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे बचत कम आकर्षक हो जाएगी तथा उपभोक्ता स्टॉक, म्यूचुअल फंड या रयिल एस्टेट की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
- **नरियात प्रतस्पर्द्धात्मकता:** कम रेपो रेट से नरियात पर मलिन वाले रटिरन में कमी आ सकती है, जिससे पूंजी का बहरिवाह हो सकता है। इससे मुद्रा कमज़ोर, आयात लागत में वृद्धि तथा नरियात प्रतस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि हो सकती है।
- **मुद्रास्फीति:** ब्याज दरों में कटौती के कारण खर्च में वृद्धि से समय के साथ कीमतें और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जिससे RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य (+/- 2% के दायरे में 4%) में वृद्धि हो सकती है।

4% मुद्रास्फीति लक्ष्य की पृष्ठभूमि:

- **चक्रवर्ती समिति (1982-85):** इस समिति का गठन तत्कालीन RBI गवर्नर मनमोहन सहि द्वारा सुखमय चक्रवर्ती के नेतृत्व में मौद्रिक नीतिकी समीक्षा के लिये किया गया था। इसकी सफिरशिं इस प्रकार थी:
 - $M3 = M1$ (जनता द्वारा धारति मुद्रा+वाणजियकि बैंकों द्वारा धारति मांग जमाराशा)+वाणजियकि बैंकों की नविल आवधकि जमाराशा
 - मौद्रिक नीतिके मुख्य उद्देश्य के रूप में मूल्य स्थरिता पर ज़ोर दिया गया।
 - आर्थिक प्राथमकिताओं में संतुलन लाने के लिये थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में 4% औसत वार्षकि मुद्रास्फीतिकी प्रस्ताव रखा गया।
 - RBI वतितपोषण पर नरिभरता कम करने के लिये बाज़ार संचालति सरकारी उधारी और सकरयि सरकारी प्रतभित्ति बाज़ार की सफिरशि की गई।
 - मुद्रास्फीतिको प्रबंधति करने के लिये मौद्रिक लक्ष्यीकरण (M3 मुद्रा आप्रति नियितरण) किया जाने की अनुशंसा की गई।
- **उरजति पटेल समिति (2014):** इससे मुद्रास्फीति लक्ष्य को औपचारकि रूप दिया गया जिसमें 4% लक्ष्य ($\pm 2\%$ बैंड) नरिधारति किया गया। यह लक्ष्य पहली बार 40 वर्ष पहले चक्रवर्ती समिति द्वारा प्रस्तावति किया गया था।
- भारत का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा, जसि वर्ष 2016 में अपनाया गया था, भारत की मौद्रिक नीतिको वैश्वकि सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है।

//

मौद्रिक नीति समिति

Monetary Policy Committee

मौद्रिक नीति समिति

- ★ **प्राधिकरण:**
 - ★ भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, **1934** के तहत मौद्रिक नीति के निर्माण हेतु अधिकृत है।
- ★ **उद्देश्य:**
 - ★ मूल्य स्थिरता और स्थिर विदेशी मुद्रा मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिये मुद्रास्फीति या ब्याज दरों को समायोजित करना।

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

- ★ **कानूनी ढाँचा:**
 - ★ संशोधित आरबीआई अधिनियम, **1934** की धारा **45ZB** के तहत।
 - ❖ केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (**MPC**) का गठन करने का अधिकार है।
 - ★ **MPC** को वर्ष में कम-से-कम चार बार बैठक करनी होती है। **MPC** के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, और वोटों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है।

संघटन

- ★ आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में।
- ★ मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर।
- ★ केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी।
- ★ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तीन व्यक्ति।

कार्य

- ★ मौद्रिक नीति समिति रेपो दर निर्धारित करती है।
 - ❖ यह वह दर है, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियाँ खरीदकर उधार देता है।
 - ❖ यह अर्थव्यवस्था में अन्य सभी ब्याज दरों के लिये एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है।
- ★ हर छह महीने में एक बार **RBI** को मुद्रास्फीति के स्रोतों और **6-18** महीनों की अवधि के लिये मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान की व्याख्या करने हेतु 'मौद्रिक नीति रिपोर्ट' नामक एक दस्तावेज प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।

क्लिक टू रीड: [उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है?](#)

नष्कर्ष:

RBI की रेपो रेट में कटौती का उद्देश्य उधार लेने की लागत को कम कर **आर्थिक विकास को बढ़ावा** देना है। हालाँकि, इससे **मुद्रास्फीति का दबाव** बढ़ सकता है, जो RBI MPC द्वारा निर्धारित 4% लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से वैश्विक अनिश्चितताओं को दृष्टिगत रखते **हुबकिस और मूल्य स्थिरता** को संतुलित किया जाना महत्वपूर्ण है।

दृष्टि भेन्स प्रश्न:

प्रश्न. आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति पर रेपो रेट में कटौती के प्रभाव पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजिये: (2020)

1. खाद्य वस्तुओं का 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI) भार (weightage) उनके 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) में दिये गए भार से अधिक है।
2. WPI, सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कि CPI करता है।
3. भारतीय रज़िर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान तथा प्रमुख नीतगित दरों के नरिधारण हेतु WPI को अपना लयिा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. यद आर.बी.आई. प्रसारवादी मौद्रकि नीतकि अनुसरण करने का नरिणय लेता है, तो वह नमिनलखिति में से क्या नहीं करेगा? (2020)

1. वैधानकि तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलति करना
2. सीमांत स्थायी सुवधि दर को बढ़ाना
3. बैंक दर को घटाना और रेपो दर को भी घटाना

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????????:

प्रश्न. संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) को परभाषति कीजिये और उसके नरिधारकों की व्याख्या कीजिये। वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपनी संभाव्य जी.डी.पी. को साकार करने से रोकते हैं? (2020)

प्रश्न. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि स्थिर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की स्थायी संवृद्धति तथा नमिन मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिये। (2019)